



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 10 मार्च, 2011/19 फाल्गुन, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 मार्च, 2011

संख्या: टी0सी0पी0-2(बी)2-1/2008(स्था)रुलज/टी पी.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तकु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-ए(3).2/97 तारीख 22-12-2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर व ग्राम योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर व ग्राम योजनाकार, वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र/ई गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध “क” का संशोधन.—(1) हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर व ग्राम योजनाकार, (वर्ग—I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध “क” में :—

(1) स्तम्भ संख्या: 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:—

पे बैंड 4: 15600—39100 रुपए जमा 7600 रुपए ग्रेड पे

(ii) संविदा पद नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :

“स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 23200 रुपए प्रतिमास”।

(2) स्तम्भ संख्या: 8 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“आयु : लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता: जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।”

(3) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे”।

(4) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सहायक नगर योजनाकारों में से प्रोन्नति द्वारा जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों :—

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला में उपाधि या डिप्लोमा, या

(ii) वास्तुकला में माध्यमिक परीक्षा पास की हो जो वास्तुकला की उपाधि या डिप्लोमा की ओर प्रेरित करे, या

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर एवं ग्राम योजना में माध्यमिक परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो, या

(iv) सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा और उपरोक्त दोनों में से किसी एक में परीक्षा पास करने के पश्चात् नगर योजना या वास्तुकला संगठन या किसी अर्हता प्राप्त नगर योजनाकार/वास्तुविद् के अधीन रेखाचित्र कार्य में तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(v) वास्तुकला/भू-दृश्य वास्तुकला में उपाधि/नैशनल डिप्लोमा, या

- (vi) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र/अर्थ शास्त्र/भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ नगर एवं ग्राम योजना में उपाधि/डिप्लोमा, और जिनका 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो प्रोन्नति द्वाराय ऐसा न होने पर सहायक नगर योजनाकारों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सहायक नगर योजनाकार व योजना अधिकारी का 12 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें सहायक नगर योजनाकार के पद पर तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संस्थानों से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर।”

(5) स्तम्भ संख्या 15—क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी :—

संकल्पना :—(क) इस पॉलिसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में नगर व ग्राम योजनाकार, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:—अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:—संविदा के आधार पर नियुक्त नगर एवं ग्राम योजनाकार को 23200/— रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्पूर्वी वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 700/—रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:—अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (नगर व ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 23200/—रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 700/—रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर.—एस. आर. छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

उपाबंध— “ख”

नगर व ग्राम योजनाकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सचिव (नगर व ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’

कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने नगर व ग्राम योजनाकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार नगर एवं ग्राम योजनाकार के रूप में से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 23200/—रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त नगर व ग्राम योजनाकार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त नगर व ग्राम योजनाकार को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त नगर एवं ग्राम योजनाकार कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उन्हें अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई. पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में उल्लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में—

1.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में —

1.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-2(B)2-1/2008 (Estt) Rules/TP dated 5.3.2011 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th March, 2011

No. TCP-2(B)2-1/2008(Estt)Rules/TP).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Town & Country Planning Town & Country Planner, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2003 notified vide this Department Notification number TCP-(A)3-2/97 dated 22.12.2003, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town & Country Planning Department, Town & Country Planner, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e Gazette, Government of Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A”.—(1) In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Department, Town & Country Planner, (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003

For the existing provision against Column No.4 the following shall be substituted, namely:-

(i) Pay scale for regular incumbents:
Pay Band-4: “Rs.15600-39100 +Rs.7600/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees:—

Rs. 23200/- P.M. as per details given in Column No.15-A

(2) For the existing provision against Column No.8 the following shall be substituted, namely:—

Age: Not applicable.

Educational Qualification: As prescribed against Column No.11 below.

(3) For the existing provision against Column No.10 the following shall be substituted, namely:—

100% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on a regular basis or by direct recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(4) For the existing provision against Column No.11 the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the Assistant Town Planners possessing following qualification.

- (i) Degree or Diploma in Architecture from a recognized Institution, or
- (ii) Has passed Intermediate Examination in Architecture leading to Degree or Diploma in Architecture, or
- (iii) Intermediate Examination in Town Planning from a recognized University/Institution or equivalent, or
- (iv) Diploma in Civil or Mechanical Engineering and three years experience in drawing work in the Town Planning or Architecture Organization or under a qualified Town Planner/Architect after passing either of the examination, or
- (v) Degree/National Diploma in Architecture/Landscape Architecture, or
- (vi) Master's Degree in Sociology/ Economic/ Geography followed by Degree/Diploma in Town and Country Planning from recognized Institution/ University and having 07

years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered, if any in the grade failing which by promotion from amongst the Assistant Town Planner having 12 years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Assistant Town Planner and Planning Officer which shall include 03 years' essential service on the post of Asstt. Town Planner, failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments/Semi Govt./Autonomous Institutions.

(5) For the existing provision against Column No.15-A the following shall be substituted, namely:—

Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Town & Country Planner, in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.PUBLIC SERVICE COMMISSION:—The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary(TCP) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(C) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :—The Town & Country Planner appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 23200/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 700/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.23200/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 700/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

© Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Re-imbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (TCP).

ANNEXURE-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Town & Country Planner & the Government of Himachal Pradesh through Secretary (TCP) to the Govt. of H.P.

This agreement is made on this day of in the year..... Between Sh/Smt.S/o/D/o

Shri.....R/o.....
, contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Secretary (TCP) to the Govt. of H.P., (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Town & Country Planner on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Town & Country Planner on contract basis for a period of 1 year commencing on day of and ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary. Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be extended/renewed
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 23200/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Town & Country Planner will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Town & Country Planner. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Town & Country Planner will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.
.....
.....
(Name and Full Address) (signature of the FIRST PARTY)
2.
.....
.....
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.
.....
.....
(Name and Full Address)
2.
.....
.....
(Name and Full Address) (signature of the SECOND PARTY)

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 3rd March, 2011

No. PBW(PH)-A(4)-8/96-III.—In pursuance of the recommendations contained in the report titled “**Performance Audit of the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP)**” Union Government (Civil) No. 4 of 2010-11, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to establish a Monitoring Cell in the Department of Irrigation & Public Health Department for monitoring of Minor Irrigation Schemes under AIBP comprising the following:-

- | | |
|--|------------------|
| 1. Chief Engineer, IPH (Concerned Zone) | Chairman |
| 2. Director, Central Water Commission
M&A Directorate, Govt. of India, Kasumpti | Member |
| 3. Superintending Engineer (concerned) | Member |
| 4. Superintending Engineers (P&I)-I&II or
Executive Engineer in P&I-II | Member |
| 5. Executive Engineer of Division implementing
MI Scheme . | Member Secretary |

2. This Monitoring Cell will ensure regular monitoring of all the MI schemes and submit monitoring report to the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

3. This Notification has already been uploaded on eGazette of H.P. Govt. Website.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (IPH).

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 5 मार्च, 2011

संख्या: सिंचाई: 11-34/2010-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा वेला इन्दौरा, तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल व मौजा	खसरा नं०	क्षेत्र (हैक्टेयर में)		
कांगड़ा	इन्दौरा	वेला इन्दौरा	1216/410/1	0	01	56
			505/1	0	03	99
			511/1	0	04	26
			513/1	0	02	10
			515/1	0	01	88
			517/1	0	02	28
			521/1	0	04	24
			522/3/1	0	05	82
			524/1	0	03	64
			523/3/1	0	00	35
			523/1/1	0	02	34
			Kittas-11	0	32	46

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 7 मार्च, 2011

संख्या: सिंचाई: 11-35/2010-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा घमोता, तहसील

इन्दौरा जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल व मौजा	खसरा नं०	क्षेत्र (हैक्टेयर मीटर में)
कांगड़ा	इन्दौरा	घमोता	162/1	0-02-55

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 7 मार्च, 2011

संख्या: सिंचाई: 11-44 / 2010-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा गगवाल, तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल व मौजा	खसरा नं०	क्षेत्र (हैक्टेयर मीटर में)
कांगड़ा	इन्दौरा	गगवाल	793/1	0-00-18
			824/1	0-02-53
			804/1	0-05-18
			805	0-01-02
			821//1	0-01-81
			807/1	0-01-00
			818/1	0-01-31
			811/1/1	0-02-28
			811/1	0-04-00
			813/1	0-03-08
			593/1	0-09-68
			599/1	0-04-05
			598/1	0-01-05
			596/1	0-02-35
			71/1	0-01-10
			70/1	0-02-98
			60/1	0-01-14
			59/1	0-01-71
			57/1	0-01-32
			58	0-02-44
			51	0-01-34
			50/1	0-01-46
			43/1	0-01-32
			42/1//1	0-01-43
			941/42/1	0-02-29
			942/42/1	0-01-31
			943/42/1	0-00-97
			54/1	0-01-44
			939/41/1	0-00-27
			940/41/1	0-00-98
			940/41/3	0-00-20
			944/42/1	0-02-59
			938/37/1	0-07-89
			953/7/1	0-03-48
			954/7/1	0-00-27
			5/1	0-17-34
			3/1	0-09-78
			2/1	0-08-64
			1/1	0-05-85
			किता-39	1-19-06

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 8 मार्च, 2011

संख्या: सिंचाई 11-1/2011 हमीरपुर.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टीहरा तहसील भोरंज जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना व वाटर टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल व मौजा	खसरा नं०	कनाल/मरले
हमीरपुर	भोरंज	टीहरा	146/1	0-05

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154 Fax. 2620152

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th March, 2011

No.SEC.16-49/2009-I-849-60 Shimla-2.—In exercise of the powers vested in it under Rule 14(e) of the H.P.Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the **first day of January, 2011 (01.01.2011)** as the date for determining whether a person is qualified to be enrolled as an elector in the electoral rolls to be prepared for the

conduct of elections to all the three tiers of Panchayati Raj Institutions of Udaipur and Keylong Sub-Divisions of Lahaul & Spiti District, Pangri Sub-Division of District Chamba and for Zila Parishad constituencies of Sub-Division Spiti of Lahaul & Spiti District, with reference to which he/she is or is not less than 18 years of age on this date.

Further the State Election Commission in exercise of powers vested in it under Article 243K of Constitution of India Section 160 of the H.P.Panchayati Raj Act, 1994, read with Rule 12 and 22 of H.P.Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, hereby directs that the special revision of electoral rolls for the conduct of elections of office bearers of Panchayati Raj Institutions of the aforesaid areas shall be undertaken and completed according to the programme given below:—

1.	Verification of electors by house to house visit by enumerators.	23rd March, 2011 to 1st April, 2011.
2.	Draft publication of electoral roll	04/04/2011
3.	Period for filing claims & objection	05/04/2011 to 11/04/2011
4.	Period for deciding claims & objections	13/04/2011 to 18/04/2011
5.	Period for filing appeals	Within seven days from the passing of the orders by the Revising Authority.
6.	Period for deciding appeals	Within Seven days from the filing of appeals
7.	Final publication of electoral roll	04/05/2011.

The Claims & Objections shall be received and decided even on holidays. After all the claims and objections received during the period have been decided the District Election Officer (Panchayat) shall cause the draft electoral roll corrected and finalized in accordance with the order passed by the Revising Authorities.

Any person aggrieved by the orders of Revising Authority may file an appeal against it to the District Election officer (Panchayats) within seven days. The District Election officer (Panchayats) shall decide the appeals within a week. After all the appeals have been disposed off by the District Election officer, he shall then cause a supplementary voter lists to be prepared and added to the electoral roll of the constituency (ies) concerned. In case of addition the serial number to the new elector in the list of the supplementary shall be the next number of the main electoral roll. In case there is no addition deletion, correction, as the case may be, supplement showing Nil shall be prepared and added.

The supplement shall be prepared in the following format:

SUPPLEMENTARY LISTS-2011

Name of Zila Parisha.....Name of Panchayat SamitiName of Gram Panchayat Ward Number and Name

ADDITION

Sr.No.	House No.	Name of Voters	Relationship	Male/Female	Age as on 1/1/2011	EPIC No.

DELITION

Sr.No.	House No.	Name of Voters	Relationship	Male/Female	Age as on 1/1/2011	EPIC No.

CORRECTION

Sr. No.	Sr. No. in Electoral Roll	Required Correction	Present Entry	Corrected Entry

The copies of the electoral roll be made available for sale @ Rs. 2/- per page to be paid in cash against receipt. However a person interested in the purchase of electoral roll ought to purchase a full electoral roll of a Gram Panchayat, as a whole.

By order ,
(DEV SWARUP)
State Election Commissioner Himachal Pradesh.

